जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 16 संख्याः 189 प्रभात हिण्डौन सिटी, शुक्रवार 10 मई, 2024 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'हमारी सरकार में मुझ पर देशद्रोह का केस हुआ, सहन करना मुश्किल, मैं खुलकर बोला कि, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता'

सचिन पायलट ने ए.एन.आई. को दिये इन्टरव्यू में खुलकर प्रदेश की राजनीति पर अपना पक्ष भी रखा

जयपुर, 9 मई (का.प्र.)। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस की राजनीति को लेकर कहा कि, "2018 में सी.एम. का फैसला मुझसे बात करके ही किया था"। सन् 2018 में अशोक गहलोत को मु.मंत्री बनाए जाने और उन्हें यह पद नहीं मिलने के सवाल पर पायलट ने कहा कि, यह पार्टी का फैसला था। वर्ष 2018 का फैसला मुझसे बात करके किया था। साथ ही पायलट ने यह भी कहा कि, किस्मत में जो लिखा है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। जो नहीं है, उसे कोई दे नहीं सकता।

न्यूज़ एजेंसी ए.एन.आई. को दिए इंटरव्यू में पायलट ने कहा–अब हम विपक्ष में हैं, सब भुलाकर काम करने की जरूरत है, किसने क्या छोटा –मोटा बोला इसे भूलकर आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है।

- "विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, पता नहीं क्या रिज़ल्ट निकलकर आता? अच्छा होता कि, मीटिंग हो जाती।"
- पायलट ने कहा कि, राजस्थान में जनता के भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, जिन पर पार्टी ने एक्शन लिया। मंत्रिपरिषद में कोई दलित मंत्री नहीं था। मैंने कहा था कि, यह गलत है, इसके बाद बदलाव हुए।
- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि, डिप्टी सी.एम. और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए हमारी ही सरकार में मुझ पर देशद्रोह का केस हुआ, इसे सहन करना मुश्किल होता है। इस पर मैं खुलकर बोला कि, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, बाद में सब चीजों का समाधान हुआ। हमने चुनाव के लिए मिलकर मेहनत की।

इसी के साथ, 2022 में विधायक दल की बैठक नहीं होने के मुद्दे पर पायलट ने कहा कि, जो हुआ, सबके सामने हुआ। पार्टी ने कमेटी बनाई, जो मुद्दे थे, उन्हें कमेटी ने लिया, मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। हाईकमान ने हमारी बातों को सुना। विधायकों की राय जानने के लिए ऑब्ज़र्वर भेजे, 25 सितंबर 2022 को दुर्भाग्य से विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर आए थे। उस बैठक का पता नहीं क्या रिज़ल्ट निकलकर आता? पर अच्छा होता कि एक बार मीटिंग हो जाती।

पायलट ने कहा कि, राजस्थान में जनता के भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, जिन पर पार्टी ने एक्शन लिया। मंत्रिपरिषद में कोई दलित मंत्री नहीं था। मैंने कहा था कि यह गलत है, इसके बाद बदलाव हुए।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि, डिप्टी सी.एम. और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए हमारी ही सरकार में मुझ पर देशद्रोह का केस हुआ, इसे सहन करना मुश्किल होता है। इस पर मैं खुलकर बोला कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, बाद में सब चीजों का समाधान हुआ। हमने चुनाव के लिए मिलकर मेहनत की।

अशोक गहलोत के साथ कड़वाहट, खींचतान और सियासी उठापटक का कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में नुकसान होने के सवाल पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस नेताओं ने प्र.मंत्री मोदी को चुनौती दी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 मई। कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक दिन पहले किए गए दावे को चुनौती दी है। जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के शीर्ष दो उद्योगपति अडाणी व अंबानी कांग्रेस को काले धन के बोरे टैम्पो में भरकर भेज रहे हैं। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने

- बुधवार को एक सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया था कि, कांग्रेस को अंबानी-अडाणी से टैम्पो में भर कई बोरे काला धन मिला है। इसके जवाब में आज कांग्रेस के नेताओं ने मोदी को अंबानी-अडाणी पर कार्यवाही करने की चुनौती दी।

कहा कि प्रधानमंत्री ने यह कहने का साहस तो किया कि उनके खुद के मित्र भ्रष्टाचार में शामिल है और वो कांग्रेस को भारतीय रुपयों के बंडल टैम्पों में भरकर भेज रहे हैं। श्रीनेत ने एक प्रेस कार्यक्रम में जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री के अधीन सभी जांच एजेन्सियां हैं जिन्हें वे मामले की जांच करने का आदेश दे सकते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'देश की जनसंख्या में 1950 व 2015 के बीच मुसलमानों की आबादी में 41.5 प्रतिशत वृद्धि हुई'

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने एक रिपोर्ट जारी कर यह दावा किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 मई। लोकसभा चुनावों के शेष चार चरणों के दौरान साम्प्रदायिक उन्माद बनाए रखने की एक हताशापूर्ण कोशिश के तहत प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक काउन्सिल ने मीडिया में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में वर्ष 1950 से वर्ष 2015 के बीच हिन्दुओं की आबादी 7.82 प्रतिशत घटी, जबकि मुस्लिमों की आबादी में 41.15 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

हालिया रिपोर्ट (पेपर) को जारी करने का समय इस कदम के इरादों और उद्देश्यों पर कई सवाल खड़े करता है। पेपर में सुझाया गया है कि देश में विविधता के पोषित का कोई सकारात्मक माहौल नहीं है।

वर्तमान में जारी लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बीच इस पेपर को सार्वजनिक किए जाने से स्पष्ट हो गया है कि इसका वास्तविक उद्देश्य सार्वजनिक चर्चाओं में हिन्दू–मुस्लिम विषय को जीवंत बनाए रखना है।

- समिति ने देश की जनसंख्या के बारे में कई और महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी पेश किये।
- पर, सबसे ज्यादा यह सवाल उठाया जा रहा है कि, लोकसभा चुनाव के बीच यह रिपोर्ट जारी करना, हिन्दू-मुस्लिम दुराव को और बढ़ावा देने का प्रयास तो नहीं?

"शेयर ऑफ रिलीज़ंस माइनॉरिटीज़ : ए क्रॉस कंट्री एनालैसिस (1950–2015)" शीर्षक वाले इस पेपर में आगे कहा गया है कि "वर्ष 1950 से 2015 के बीच बहुसंख्यक हिन्दुओं की आबादी 7.82 प्रतिशत घटी (84.68 प्रतिशत से 78.06 प्रतिशत।)। वर्ष 1950 में मुस्लिम आबादी का शेयर 9.84 प्रतिशत था जो वर्ष 2015 में 14.09 प्रतिशत तक बढ़ गया।" यह उनकी आबादी के शेयर में 43.15 प्रतिशत बढ़ोतरी थी।

पेपर के अनुसार, इस दौरान ईसाईयों की आबादी 2.24 से 2.36 प्रतिशत तक बढ़ी, यानि कि वर्ष 1950 और वर्ष 2015 के बीच उनकी आबादी का शेयर 5.38 प्रतिशत बढ़ा।

सिखों की आबादी इस दौरान 1.24 प्रतिशत से 1.85 प्रतिशत बढ़ी जो कुल आबादी में उनके शेयर की 6.58 वृद्धि थी। भारत की पारसी आबादी में 85 प्रतिशत की भारी कमी आई। वर्ष 1950 में आबादी में उनका शेयर 0.03 प्रतिशत था जा वर्ष 2015 में 0.004 हो गया।

पेपर में कहा गया कि उसके डेटा संकेत देते हैं कि समाज में विविधता को पोषित करने के लिए सकारात्मक वातावरण है, लेकिन यह भी कहा गया है कि समाज के वंचित वर्गों को किसी ऊर्ध्वगामी सहारे के बिना बेहतर जीवन देना संभव नहीं है।

पेपर में ध्यान दिलाया गया कि बहुसंख्यक आबादी के शेयर में कमी और अल्पसंख्यकों की आबादी के शेयर में हुई बढ़ोतरी से यह पता चलता है कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी का चुनावी फोकस बिहार व महाराष्ट्र पर है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 मई। महाराष्ट्र और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में, जिन सीटों से भाजपा खुद चुनाव लड़ रही है, वह उन सीटों पर जीतने के प्रति आश्वस्त नज़र आ रही है लेकिन, इन दोनों राज्यों में अपने गठबंधन साथियों की जीत पर उसको उतना विश्वास नहीं है। दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 98 लोकसभा सीटे हैं।

वर्ष 2019 के चुनावों में नेशनल डैमोक्रेटिक एलायंस (एन.डी.ए.) ने, महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीटें और बिहार में 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। सत्तारुढ़ गठबंधन शायद इस संख्या को कायम न रख सके, इस चिंता के कारण, इन दोनों राज्यों में, अगले कुछ दिनों के लिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक आक्रामक प्रचार अभियान को अंतिम रुप दे दिया गया है। यह दिलचस्प है कि, इन राज्यों में, प्रधानमंत्री अपना ध्यान उन चुनाव क्षेत्रों पर केन्द्रित करेंगे जहां से गठबंधन साथियों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक महाराष्ट्र में 14 और बिहार में 6 रैलियां की हैं। यह संख्या अब बढ़ेगी क्योंकि वे अब महाराष्ट्र में 4 और बिहार में तीन और रैलियां करेंगे।

- पर, उल्लेखनीय बात यह है कि, दोनों राज्यों में प्र.मंत्री का फोकस रैली व आम सभा कि दृष्टि से गठबंधन की साथी पार्टियों की सीटों पर है।
- बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जद (यू), चिराग पासवान की पार्टी एल.जे.पी. तथा जीतन राम मांझी की पार्टी एच.ए.एम. की सीटों पर मोदी सघन प्रचार करेंगे।
- इसी प्रकार महाराष्ट्र में प्र.मंत्री गठबंधन की घटक पार्टियों की छः सीटों पर रैली व आम सभाएं करेंगे। पर, अजीत पवार की पार्टी और शिव सेना (शिंदे) की सीटें अभी तक मोदी जी के अभियान से अछूती रही हैं।

बिहार में अगले सोमवार तक उनकी कुल 9 जनसभाएं होंगी इनमें से पांच जनसभाएं उन सीटों पर होंगी जहां से भाजपा के गठबंधन सहयोगी, नीतीश कुमार की जदयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (एल.जे.पी.) और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एच.ए.एम.) चुनाव लड़ रही हैं।

महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने अभी तक चार सभाओं को संबोधित किया है, जहां से गठबंधन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उनको दो और सीटें, नासिक और कल्याण, जहां से भाजपा के सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं, में सभाओं को संबोधित करना है। अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) प्रधानमंत्री के "ऑरबिट" से किसी कारणवश बाहर रह गई है क्योंकि, मोदी ने अभी तक किसी एन.सी.पी. प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं किया है।

भाजपा, अपने दम पर, महाराष्ट्र में 27 सीटों पर और बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा के लिए जदयू, बिहार की कमज़ोर कड़ी लगती

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी और राहुल गांधी सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 मई। जनता को जागरूक रखने को लेकर एक गंभीर पहल के तहत सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी. लोकुर, ए.पी. शाह और पत्रकार एन. राम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव 2024 पर एक सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित

- यह आमंत्रण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी. लोकुर, ए.पी. शाह और पत्रकार एन. राम ने भेजा है।

किया है। अपने आमंत्रण में इन लोगों ने कहा है कि जनता ने सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के सिर्फ आरोपों और चुनौतियों के बारे में सुना है, लेकिन उसने इन दोनों की कोई "अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया" नहीं सुनी है।

जस्टिस लोकुर, जस्टिस शाह और पत्रकार एन. राम द्वारा लिखे गए पत्र में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारी मतदान के बावजूद बंगाल में वोटर मुखरित नहीं है, अपनी राय बताने के बारे में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 मई। ममता बनर्जी एक शक्तिशाली नेता हैं, लेकिन वह वर्तमान में अपने पूरे दमखम के साथ तृणमूल कांग्रेस की खराब छवि को उज्ज्वल बनाने में लगी हैं।

ममता बनर्जी के बंगाल में उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) स्कूल की नौकरियों के घोटाले, राशन वितरण घोटाले और संदेशखाली की घटना पर आए कोर्ट के विपरीत फैसलों के बाद अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है। कोर्ट के फैसलों ने बड़े पैमाने पर भूमि कब्जों, धन ऐंठने और बलात्कार के आरोपों को उजागर किया है।

तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता की पत्नी ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की है कि उसे एक खाली कागज पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए दिया गया जिसके बाद उस पेपर पर रेप की शिकायत लिखकर स्थानीय पुलिस में दर्ज करायी गई। तृणमूल कांग्रेस इस कथित झूठे आरोप को लेकर हल्ला कर रही है।

भाजपा नेता अब यह कह रहे हैं कि घटनाएं एक लम्बे अर्से पहले हुई, जब भाजपा के कार्यकता या नेता संदेशखाली के दूरस्थ एवं पृथक इलाके में घुस भी नहीं पाते थे। वे एक स्थानीय महिला पर शिकायत लिखने का दबाव कैसे बना सकते हैं। एक अकेली महिला भ्रामक शिकायत दर्ज करा सकती है, लेकिन उन हजारों महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे जिन्होंने लगातार हो रहे उत्पीड़न और निरंतर दी जा रही धमकियों के विरोध में जुलूस निकाला था। उन्होंने तृणमूल के गुण्डों के खिलाफ मारपीट और हत्याओं की शिकायत की थी।

- पर, तृणमूल कांग्रेस का, संदेशखाली में "मास रेप" व महिलाओं की पिटाई की बात को पूर्णतया झूठा व कपोत कल्पित साबित करने का प्रयास जनता के गले नहीं उतर रहा है।
- इसी प्रकार राजभवन की एक महिला कर्मचारी द्वारा गवर्नर पर बलात्कार का आरोप भी मुसीबत पैदा कर रहा है, तृणमूल पार्टी के लिये।
- राज्यपाल ने अपनी केरल यात्रा से लौटकर, राजभवन के सी.सी.टी.वी. के कवरेज का रिकॉर्ड अपने कब्जे में किया तथा शहर के सभ्रांत व प्रभावशाली लोगों को दिखाया और अपनी जिंदादिली साबित की।
- राज्यपाल ने राज्य की पुलिस की ही नहीं, मंत्रियों की एंट्री भी बंद कर दी राजभवन में।

एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) अधिकारी जब तृणमूल नेता शेख शाहजहाँ से बात करने संदेशखाली में उसके घर गए थे, तब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से तुरन्त ही भागना पड़ा था। उसके बाद शेख शाहजहाँ और उसके साथी गिरफ्तार किए गए तथा अब वे हवालात में हैं।

संदेशखाली में किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता के लिए प्रवेश संभव नहीं था। इस पर कई सच व झूठ हैं। संदेशखाली में हुई घटनाओं से ममता बनर्जी इन्कार कर रही हैं और उन घटनाओं के प्रमाण मांग रही है जिन्होंने लोगों को आंदोलन के लिए उकसाया। ममता की यह बात शायद जनता के गले नहीं उतरेगी।

दूसरी तरफ कुछ समय पहले की बात है बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनन्द बोस के राजभवन में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने स्थानीय पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई थी उस पर यौन हमला किया गया था। उस महिला से प्राप्त रिपोर्ट के बाद तत्काल कार्यवाही करते हुए राज्य की पुलिस हरकत में आ गई थी और राजभवन मे मामले की जाँच करने पहुँच गई थी।

शिकायत दर्ज कराने के बाद अगले दिन राज्यपाल बोस को केरल उनके गृह प्रदेश में जाना था, जो कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गए थे।

अपनी संक्षिप्त यात्रा से वापस लौटने के बाद राज्यपाल ने कुछ सी.सी. टी.वी. फुटेज जारी करने की धमकी दी,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर के दर्शन किये

अयोध्या, 9 मई। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार को अयोध्या के राम मंदिर में गए और वहां भगवान राम के समक्ष शीश नवाया और प्रार्थना की। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थित मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था।

- राज्यपाल आरिफ मोहम्मद की शुक्रवार को कुछ तस्वीरें सामने आईं हैं, जिनमें वो रामलला के समक्ष शीश झुकाकर प्रार्थना कर रहे हैं।

उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश–दुनिया के हजारों गणमान्य मौजूद रहे थे। बुधवार दोपहर अयोध्या पहुंचे खान ने राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में गए और विशेष प्रार्थना की तथा भगवान राम के सामने शीश नवाया।

"इशु लैस" चुनाव ने सभी को डरा रखा है, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, या पत्रकार, या अफसर!

सभी को डर है कि, अब तक प्रचलित कई राजनैतिक धारणाएं व किंवदंतियां नेस्ताबूद हो सकती हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजों से

-विशेष प्रतिनिधि द्वारा-

जयपुर, 9 मई। पिछले विधानसभा चुनाव में "इशू" स्पष्ट था, ऊपर से शुरु होकर ज़मीनी स्तर पर फैला सरकारी "करप्शन" (भ्रष्टाचार)। इस भ्रष्टाचार को स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं था, चाहे मु.मंत्री हो या विधायक, या फिर तहसीलदार, पटवारी या मुख्य सचिव स्तर के उच्चतम अधिकारी। बड़ा भ्रष्टाचार, एक सामान्य आदमी की ज़िंदगी को शायद सीधा प्रभावित नहीं करता, जैसे बोफोर्स तोपों की खरीद। परंतु पटवारी, थानेदार आदि, तहसील व उनसे भी छोटे स्तर के प्रशासनिक अधिकारी का भ्रष्टाचार एक आदमी को ज़िंदगी को रोज छूता है व अपने घाव छोड़ता है। धीमी आँच की तरह सामान्य आदमी को अन्दर ही अन्दर झुलसाता रहता है और चुनाव के समय लावा की तरह फूटकर निकलता है। आम आदमी का यह आक्रोश गहलोत सरकार को ले बैठेगा, यह साफ दिख रहा था। चाहे तत्कालीन मु.मंत्री ने बेइन्तहा पैसा खर्च किया, उस चुनाव में अपनी "इमेज" बनाने

- इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी वो उन्माद व उत्साह नहीं दिखा जो 2014 व 2019 के चुनावों में दिखा था। यही नहीं, राम मंदिर के मुद्दे पर भी कोई उन्माद नहीं दिखा।
- पर, सबसे बड़ी बात यह रही कि, एंटी मोदी या एंटी भाजपा लहर भी नज़र नहीं आई। राहुल गांधी के तमाम प्रयासों के बाद भी इंडिया गठबंधन वैसा "नैरेटिव" तैयार नहीं कर सका जो जनता में लहर पैदा कर देता।
- यही वजह है कि, मतदान के प्रति भारी उदासीनता देखी गई। यही नहीं, विधानसभा चुनावों में गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के प्रति जो भारी नाराज़गी थी वह भी हल्की पड़ती दिखी।
- फिर भी गहलोत को एक बात का डर है कि, अगर भाजपा को सभी 25 सीटें मिली तो कभी गहलोत समर्थक रहे नेता भाजपा के समक्ष अपने नम्बर बढ़वाने के लिए मुंह खोलने लगेंगे और फिर भ्रष्टाचार के कई कांड उजागर होंगे। फोन टैपिंग, पेपर लीक, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे कई प्रकरण हैं, जिन पर गहलोत को लपेटा जा सकता है।

के लिये तथा, "इमेज" बनाने वाले विशेषज्ञों, जैसे डिज़ाइन बॉक्स आदि को खुली छूट दी, उनके छवि सुधार अभियान की रणनीति बनाने में और उसे क्रियान्वित करवाने में।

पर, वर्तमान लोकसभा चुनाव में न प्र.मंत्री मोदी के लिये वो उन्माद भरा उत्साह है, जो 2013 व 2019 में साफ दिखता था, ना ही ऐसा उन्माद राम मंदिर के बारे में है। पर, दूसरी ओर यह भी सही है कि, "एन्टी मोदी", या "एन्टी भाजपा" उन्माद या "सेन्टीमैंट" भी नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि, राहुल गांधी के अथक प्रयासों के बावजूद "इंडिया गठबंधन" कोई ऐसा "नैरेटिव" (कथानक) तैयार नहीं कर सका, जो जनता को झकझोर देता। एक ऐसा अतिरेक पैदा कर देता जो जनता को पोलिंग बूथ तक आने के लिये उत्साहित करता या मजबूर करता। उदासीनता के कारण, वोट डालने कुछ जनता आयी भी, कुछ नहीं भी आई।

यह गहलोत की खुशनसीबी है कि, जनता की स्मृति बहुत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिवकाशी की पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, 8 की मौत

चेन्नई, 9 मई। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में गुरुवार को एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट में पांच महिलाओं सहित आठ श्रमिकों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए।

हादसा शिवकाशी के पास सेंगामालापट्टी गांव में श्री सुदर्शन फायरवर्क्स में हुआ। सरवनन के स्वामित्व वाली इकाई में 40 से अधिक

- मृतकों में पांच महिला श्रमिक भी शामिल हैं, हादसे में 12 अन्य घायल हुए।

वर्किंग शेड हैं।

गुरुवार दोपहर जब कर्मचारी वर्किंग शेड में फैंसी किस्म के पटाखे बना रहे थे, तभी घर्षण के कारण विस्फोट हो गया। आग आसपास के शेडों में फैल गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन और बचाव सेवा कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।

घायलों को शिवकाशी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।